IJARSCT

International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology

International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal

ISSN: 2581-9429 Volume 6, Issue 1, May 2026 Impact Factor: 8.2

fdlku ØfMV dkM ;ktuk% fdlkuk d vkfFkd l'kfädj.k dk ,d ek/;e

j[kk jkuh and Mkñ f'kodekj

शोधार्थी, श्री जे जे टी विश्वविद्यालय, झुंझुनूं

, शोध निर्देशक, श्री जे जे टी विश्वविद्यालय, झुंझुनूं

lkjka'k% कृषि क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, जहां अधिकांश जनसंख्या अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। किसानों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा किसान क्रेडिट कार्डयोजना की शुरुआत की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य किसानों को सरल, सुलभ और समय पर ऋण सुविधा उपलब्ध कराना है। प्रस्तुत शोध का उद्देश्य किसान क्रेडिट कार्ड योजना की भूमिका का किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण के संदर्भ में विश्लेषण करना है।

यह अध्ययन दर्शाता है कि केसीसी योजना ने किसानों को साहूकारों और अनौपचारिक ऋण स्रोतों पर निर्भरता से मुक्त करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसके माध्यम से किसानों को कम ब्याज दर पर ऋण प्राप्त होता है, जिससे वे कृषि निवेश, बीज, उर्वरक, उपकरण आदि पर समय पर खर्च कर पाते हैं। परिणामस्वरूप कृषि उत्पादकता में वृद्धि होती है तथा किसानों की आय और जीवन स्तर में सुधार देखा जाता है।

इसके अतिरिक्त, यह योजना वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के साथ—साथ किसानों में आत्मनिर्भरता और आर्थिक सुरक्षा की भावना को भी मजबूत करती है। हालांकि, योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में जागरूकता की कमी, बैंकिंग प्रक्रियाओं की जटिलता और सीमित पहुंच जैसी चुनौतियाँ भी सामने आती हैं। अतः निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण का एक प्रभावी साधन है, बशर्ते इसकी पहुंच और कार्यान्वयन को और अधिक सुदृढ़ किया जाए।

eq[; 'kCn% किसान क्रेडिट कार्ड, आर्थिक सशक्तिकरण, कृषि ऋण, वित्तीय समावेशन, कृषि उत्पादकता, ग्रामीण विकास।

ifjp;% भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहाँ आज भी जनसंख्या का एक बड़ा भाग अपनी आजीविका के लिए कृषि एवं उससे संबंधित गतिविधियों पर निर्भर है। कृषि क्षेत्र न केवल खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करता है, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। इसके बावजूद, भारतीय किसान लंबे समय से वित्तीय

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429 Volume 6, Issue 1, May 2026 Impact Factor: 8.2

संसाधनों की कमी, अनिश्चित आय, प्राकृतिक जोखिम तथा ऋण की सीमित उपलब्धता जैसी समस्याओं का सामना करते रहे हैं।

किसानों के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती समय पर और सस्ती दरों पर ऋण की उपलब्धता रही है। पारंपरिक रूप से किसान अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए साहूकारों एवं अन्य अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भर रहते थे, जो उच्च ब्याज दरों के कारण उन्हें ऋण जाल में फँसा देते थे। इस स्थिति ने किसानों की आर्थिक स्थिति को कमजोर किया और उनकी उत्पादक क्षमता को भी प्रभावित किया। इन्हीं समस्याओं के समाधान के लिए भारत सरकार ने वर्ष 1998–99 में किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की। इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को सरल, सुलभ एवं समयबद्ध ऋण सुविधा प्रदान करना है, ताकि वे अपनी कृषि आवश्यकताओं जैसे बीज, उर्वरक, कीटनाशक एवं कृषि उपकरणकृके लिए आसानी से वित्तीय संसाधन प्राप्त कर सकें।

किसान क्रेडिट कार्ड योजना के माध्यम से किसानों को एक लचीली ऋण प्रणाली प्रदान की जाती है, जिसमें वे अपनी आवश्यकतानुसार ऋण ले सकते हैं और उपयोग के अनुसार उसे वापस कर सकते हैं। यह योजना न केवल किसानों को औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से जोड़ती है, बल्कि उन्हें वित्तीय समावेशन की दिशा में भी आगे बढ़ाती है। इसके अतिरिक्त, केसीसी योजना ने किसानों की साहूकारों पर निर्भरता कम करने, कृषि निवेश को बढ़ाने तथा उत्पादन एवं आय में वृद्धि करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह योजना किसानों को आत्मनिर्भर बनाने और उनके जीवन स्तर में सुधार लाने का एक प्रभावी माध्यम बनकर उभरी है। हालांकि, योजना के बावजूद कई चुनौतियाँ अभी भी मौजूद हैं, जैसेकृजागरूकता की कमी, बैंकिंग प्रक्रियाओं की जटिलता, तथा छोटे एवं सीमांत किसानों तक इसकी सीमित पहुँच। इस संदर्भ में, प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य किसान क्रेडिट कार्ड योजना के किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण पर प्रभाव का विश्लेषण करना है, जिससे यह समझा जा सके कि यह योजना किस हद तक किसानों की आय, उत्पादन और जीवन स्तर में सुधार लाने में सफल रही है।

lkfgR; leh{kk विभिन्न शोधों में पाया गया है कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना ने कृषि वित्त प्रणाली को मजबूत किया है। कुछ अध्ययनों के अनुसार, किसान क्रेडिट कार्ड से किसानों की आय और उत्पादकता में वृद्धि हुई है। अन्य शोध बताते हैं कि यह योजना साहूकारों पर निर्भरता को कम करने में सहायक रही है। हालांकि, कई शोध यह भी दर्शाते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता की कमी और बैंकिंग प्रक्रियाओं की जटिलता योजना की प्रभावशीलता को सीमित करती है।

,l- pVth ½2015½ ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना के प्रभाव का अध्ययन कृषि क्षेत्र में ऋण वितरण को सरल बनाने के उदेश्य से किया, जो भारत में कृषि ऋण सुधार का एक प्रमुख प्रयास है। इस अध्ययन में जिला–स्तरीय पैनल डेटा एवं परिवार–स्तरीय आंकड़ों का उपयोग करते हुए कृषि उत्पादन, प्रौद्योगिकी अपनाने

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429 Volume 6, Issue 1, May 2026 Impact Factor: 8.2

तथा पारिवारिक परिणामों पर इसके प्रभाव का विश्लेषण किया गया। विश्लेषण बताता हैं कि केसीसी योजना ने कृषि उत्पादन में वृद्धि की, विशेष रूप से देश की प्रमुख फसल धान उत्पादन में। इसके साथ ही उच्च उत्पादक किस्म के बीजों के उपयोग में भी वृद्धि देखी गई, जो इस बात का संकेत है कि तकनीक को सफलतापूर्वक अपनाया गया है। अध्ययन से यह भी ज्ञात हुआ कि कृषि परिवारों की आय में वृद्धि हुई है, जो यह दर्शाता है कि केसीसी योजना ने गरीब किसानों के आर्थिक कल्याण पर सकारात्मक प्रभाव डाला है। परिवारों द्वारा बैंक ऋण लेने में वृद्धि हुई, जिससे आय और उत्पादन में सुधार हुआ। यह ग्रामीण परिवारों की आर्थिक स्थिति सुधारने एवं कृषि उत्पादकता बढ़ाने में इस योजना की प्रभावशीलता का सशक्त प्रमाण है।

pnk ¼2020½ ने भारत के विभिन्न राज्यों तथा बिहार के जिलों में केसीसी ऋण वितरण के निर्धारकों का आलोचनात्मक अध्ययन किया। अध्ययन में यह पाया गया कि जिन राज्यों में प्रारंभिक स्तर पर कृषि ऋण की उपलब्धता अधिक थी, वहाँ बाद में केसीसी ऋण वितरण में भी वृद्धि देखी गई। हालांकि, अध्ययन से यह भी स्पष्ट हुआ कि यद्यपि केसीसी योजना ने ऋण पहुँच को बढ़ाया, लेकिन राज्य एवं जिला स्तर पर कृषि उत्पादकता में प्रत्यक्ष वृद्धि का स्पष्ट प्रमाण नहीं मिला। अतः यह कहा जा सकता है कि योजना ने वित्तीय समावेशन को तो बढ़ावा दिया है, परंतु इसके कृषि विकास पर प्रत्यक्ष प्रभाव मिश्रित रहा है।

feJk ,oa vU; ¼2021½ ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना का विश्लेषण किया, यह एक विशिष्ट सरकारी पहल है, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीयकृत वित्तीय संस्थानों के माध्यम से किसानों को अल्पकालिक कृषि ऋण उपलब्ध कराना है। अध्ययन से यह पाया गया कि योजना के प्रभाव सकारात्मक हैं, लेकिन विभिन्न जिलों में ऋण वृद्धि दर में काफी भिन्नता पाई जाती है। कृषि उत्पादन, ऋण वसूली तथा सतत विकास को सुनिश्चित करने के लिए ऋण की पहुँच को बढ़ाना आवश्यक है। इसके लिए स्थानीय सरकारों एवं वित्तीय संस्थानों को ऐसा वातावरण तैयार करना चाहिए जो किसानों के लिए ऋण उपलब्धता को सुगम बनाए। अध्ययन में क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने तथा कृषि ऋण के तेज प्रवाह हेतु लक्षित हस्तक्षेप की आवश्यकता पर बल दिया गया है।

dekj ,oa vU; ¼2023½ ने पूर्वी भारत में केसीसी योजना तक पहुँच के निर्धारकों तथा इसके कृषि आदानों के उपयोग एवं किसान परिवारों की आय पर प्रभाव का अध्ययन किया। इस अध्ययन में बड़े पैमाने पर ग्रामीण परिवारों के सर्वेक्षण डेटा का विश्लेषण किया गया। परिणामों से ज्ञात हुआ कि जिन किसानों की सामाजिक–आर्थिक एवं जनसांख्यिकीय स्थिति बेहतर है, उनकी केसीसी तक पहुँच अधिक है। केसीसी से कृषि आदानों के उपयोग में वृद्धि हुई, किसानों की आय में वृद्धि हुई, विशेष रूप से छोटे एवं सीमांत किसानों को अधिक लाभ मिला। केसीसी के माध्यम से किसानों की साहूकारों पर निर्भरता लगभग 25 प्रतिशत तक कम हुई है, जिससे वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिला तथा ग्रामीण कृषि विकास को मजबूती मिली।

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429
Volume 6, Issue 1, May 2026
Impact Factor: 8.2

v/;;u ds mís';

1. किसान क्रेडिट कार्ड योजना के प्रभाव का विश्लेषण करना।
2. किसानों की आय एवं उत्पादन पर इसके प्रभाव का अध्ययन करना।
3. साहूकारों पर निर्भरता में कमी का मूल्यांकन करना।
4. योजना के क्रियान्वयन में आने वाली समस्याओं की पहचान करना।

ifjdYiuk

H_1: केसीसी योजना किसानों की आय में वृद्धि करती है।

H_2: केसीसी योजना कृषि उत्पादन को बढ़ाती है।

H_3: केसीसी योजना साहूकारों पर निर्भरता कम करती है।

vuqla/kku i)fr

vuqla/kku dk çdkj % यह अध्ययन वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक प्रकृति का है।

laed ds lzksr %

çkFkfed laed % किसानों से साक्षात्कार और प्रश्नावली के माध्यम से जानकारी एकत्रित की गई।

f}rh;d laed % सरकारी रिपोर्ट, बैंकिंग संस्थानों के दस्तावेज, शोध पत्र और जर्नल का उपयोग किया गया।

ueuk p;u %

v/;;u {ks= % हरयाणा राज्य के ग्रामीण क्षेत्र (रोहतक जिला)

ueuk vkdkj % 60 किसान

ueuk fof/k % सरल यादृच्छिक नमूना

MsVk laxzg.k ds midj.k

- संरचित प्रश्नावली
- व्यक्तिगत साक्षात्कार
- अवलोकन

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429 Volume 6, Issue 1, May 2026 Impact Factor: 8.2

fo'y"k.k dh fof/k

- प्रतिशत विधि
- तालिकीय विश्लेषण

led fo'y"k.k इस अध्ययन में किसान क्रेडिट कार्डयोजना के माध्यम से किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण का आकलन करने के लिए 60 चयनित किसानों से प्राथमिक आंकड़े एकत्रित किए गए। आंकड़ों का विश्लेषण मुख्यतः प्रतिशत विधि तथा तालिकीय प्रस्तुति के माध्यम से किया गया, जिससे योजना के प्रभाव का स्पष्ट एवं तुलनात्मक अध्ययन संभव हो सका।

1- fdlku ØfMV dkM dh miyC/krk

rkfydk 1 dlhlh dh miyC/krk

J.kh	çfr'kr
उपलब्ध	65
उपलब्ध नहीं	35

अध्ययन के अनुसार, कुल उत्तरदाताओं में से लगभग 65 प्रति"ात किसानों के पास किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध है, जबकि 35 प्रति"ात किसान अभी भी इस सुविधा से वंचित हैं। यह दर्शाता है कि योजना की पहुँच संतोषजनक तो है, परंतु अभी भी इसका पूर्ण कवरेज नहीं हो पाया है।

विशेष रूप से छोटे एवं सीमांत किसान जागरूकता की कमी, बैंकिंग प्रक्रियाओं की जटिलता तथा आवश्यक दस्तावेजों की अनुपलब्धता के कारण इस योजना से लाभान्वित नहीं हो पा रहे हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि योजना के विस्तार के लिए लक्षित प्रयासों की आवश्यकता है।

2- vk; ij çHkko

rkfydk 2 dlhlh dk vk; ij çHkko

J.kh	çfr'kr
आय में वृद्धि	60
कोई परिवर्तन नहीं	25
मामूली वृद्धि	15

आय के संदर्भ में विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि लगभग 60 प्रति"ात किसानों ने आय में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की। 25 प्रति"ात किसानों ने आय में कोई विशेष परिवर्तन नहीं बताया। जबकि 15 प्रति"ात किसानों ने मामूली

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429
Volume 6, Issue 1, May 2026
Impact Factor: 8.2

वृद्धि का अनुभव किया। यह परिणाम संकेत देते हैं कि केसीसी के माध्यम से प्राप्त ऋण का उपयोग मुख्यतः उत्पादक कृषि कार्यों जैसे उन्नत बीज, उर्वरक एवं सिंचाई साधनों में किया जा रहा है। इससे कृषि उत्पादकता और आय दोनों में सकारात्मक वृद्धि देखी गई। हालांकि जिन किसानों की आय में वृद्धि नहीं हुई, उनके मामलों में ऋण का सीमित उपयोग, प्राकृतिक जोखिम या विपणन संबंधी समस्याएँ प्रमुख कारण हो सकते हैं।

3- lkgwdkjksa ij fuHkZjrk esa deh

rkfydk 3 lkgwdkj ij fuHkZjrk

J.kh	çfr'kr
निर्भरता कम हुई	70
अभी भी निर्भर	30

अध्ययन में पाया गया कि लगभग 70 प्रति”ात किसानों ने केसीसी प्राप्त करने के बाद साहूकारों पर अपनी निर्भरता कम कर दी है। वहीं, 30 प्रति”ात किसान अभी भी आंशिक रूप से गैर–औपचारिक स्रोतों (साहूकार, मित्र, रिश्तेदार) पर निर्भर हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि बैंक से ऋण प्राप्त करने में समय लगता है, प्रक्रिया जटिल होती है तथा तत्काल नकद आवश्यकता के समय औपचारिक संस्थान पर्याप्त तेजी से सहायता नहीं दे पाते। फिर भी, यह स्पष्ट है कि केसीसी योजना किसानों को उच्च ब्याज दरों के शोषण से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

4- —f"k mRiknu ij çHkko

rkfydk 4 mRiknu ij çHkko

J.kh	çfr'kr
उत्पादन बढ़ा	65
नहीं बढ़ा	35

समय पर और सुलभ ऋण उपलब्धता के कारण किसानों को कृषि निवेश में सुधार करने का अवसर मिला है। लगभग 65 प्रति”ात किसानों ने कृषि उत्पादन में वृद्धि की पुष्टि की। किसानों ने बताया कि वे अब बेहतर गुणवत्ता के बीज, उर्वरक, कीटनाशक एवं आधुनिक कृषि उपकरणों का उपयोग कर पा रहे हैं। इससे न केवल उत्पादन में वृद्धि हुई, बल्कि कृषि की लागत–प्रभावशीलता भी बेहतर हुई है। यह निष्कर्ष इस बात को पुष्ट करता है कि केसीसी योजना केवल वित्तीय सहायता नहीं, बल्कि उत्पादकता वृद्धि का माध्यम भी है।

Copyright to IJARSCT
www.ijarsct.co.in
DOI: 10.48175/IJARSCT-34732

5- ;kstuk ds fØ;kUo;u esa leL;k,¡

rkfydk 5 leL;k,¡

leL;k	**çfr'kr**
जटिल प्रक्रिया	40
जागरूकता की कमी	30
दस्तावेजीकरण	20
अन्य	10

यद्यपि योजना लाभकारी सिद्ध हुई है, फिर भी इसके प्रभावी क्रियान्वैयन में कुछ प्रमुख बाधाएँ सामने आईं। 40 प्रति’’ात किसानों ने बैंकिंग प्रक्रियाओं को जटिल बताया। 30 प्रति’’ात किसानों ने जागरूकता की कमी को मुख्य समस्या माना। 20 प्रति’’ात कसानों ने दस्तावेजीकरण को कठिन बताया। शेष 10 प्रति’’ात किसानों ने अन्य समस्याएँ बताईं, जैसे बैंक कर्मचारियों का असहयोग, ऋण स्वीकृति में देरी, तथा तकनीकी समस्याएँ। इन समस्याओं से स्पष्ट है कि प्रशासनिक स्तर पर सुधार की आवश्यकता है, ताकि योजना का लाभ अधिकाधिक किसानों तक सरलता से पहुँच सके।

अंततः, डेटा विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। यह योजना किसानों को सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध कराकर उनकी आय और उत्पादन में वृद्धि करती है तथा उन्हें साहूकारों के शोषण से बचाती है। हालांकि, योजना की प्रभावशीलता को और बढ़ाने के लिए जागरूकता, सरल प्रक्रियाओं और बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था की आवश्यकता है।

ppkZ प्रस्तुत अध्ययन से यह स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। यह योजना किसानों को औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से जोड़कर उन्हें सुलभ, समयबद्ध एवं कम ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराती है, जिससे उनकी वित्तीय निर्भरता अनौपचारिक स्रोतों पर कम होती है। अध्ययन के आंकड़े यह संकेत देते हैं कि केसीसी के माध्यम से प्राप्त ऋण का उपयोग मुख्यतः उत्पादक कृषि गतिविधियों में किया जा रहा है, जिससे न केवल कृ षि उत्पादन में वृद्धि हुई है, बल्कि किसानों की आय और बचत क्षमता में भी सुधार हुआ है। इस प्रकार, यह योजना केवल ऋण वितरण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह कृषि विकास और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण का भी एक प्रभावी माध्यम बनकर उभरी है। साथ ही, यह भी पाया गया कि केसीसी योजना ने किसानों को साहूकारों के उच्च ब्याज दरों वाले ऋण जाल से बाहर निकालने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इससे किसानों में आत्मविश्वास और आर्थिक स्वतंत्रता की भावना विकसित हुई है, जो दीर्घकालिक

ISSN: 2581-9429
Volume 6, Issue 1, May 2026
Impact Factor: 8.2

सशक्तिकरण के लिए आवश्यक है। हालांकि, अध्ययन में कुछ महत्वपूर्ण चुनौतियाँ भी सामने आई हैं। विशेष रूप से

- योजना के प्रति अपर्याप्त जागरूकता,
- बैंकिंग प्रक्रियाओं की जटिलता,
- दस्तावेजीकरण संबंधी कठिनाइयाँ,
- ऋण स्वीकृति में देरी

ये सभी कारक योजना के प्रभाव को सीमित करते हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि केसीसी योजना की सफलता केवल इसके प्रावधानों पर नहीं, बल्कि इसके प्रभावी एवं पारदर्शी क्रियान्वयन पर निर्भर करती है। यदि इन बाधाओं को दूर किया जाए, तो यह योजना अधिक व्यापक स्तर पर किसानों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकती है।

fu"d"k%

अध्ययन के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना भारतीय किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण का एक प्रभावी एवं व्यवहारिक साधन है। यह योजना किसानों को न केवल सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध कराती है, बल्कि उन्हें आधुनिक कृषि निवेश अपनाने, उत्पादन बढ़ाने और आय में स्थायित्व लाने में भी सहायता करती है। इसके परिणामस्वरूप किसानों के जीवन स्तर में सुधार, जोखिम वहन क्षमता में वृद्धि तथा आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिला है। हालांकि, योजना की वर्तमान स्थिति को देखते हुए यह भी स्पष्ट है कि इसकी पूर्ण क्षमता का अभी तक पूर्ण उपयोग नहीं हो पाया है। विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों तक इसकी पहुँच सीमित है। अतः यदि योजना के क्रियान्वयन में सुधार किया जाए, जागरूकता को बढ़ाया जाए और प्रक्रियाओं को सरल बनाया जाए, तो ज्ञब्ब योजना भविष्य में कृषि क्षेत्र के सतत विकास का एक सशक्त स्तंभ सिद्ध हो सकती है।

l|>ko%

योजना की प्रभावशीलता और पहुँच को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत किए जाते हैं:–

tkx:drk e¨ of) & विशेष रूप से ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों में किसानों के बीच केसीसी योजना के लाभ, प्रक्रिया एवं पात्रता के बारे में व्यापक जागरूकता अभियान चलाए जाएँ।

DOI: 10.48175/IJARSCT-34732

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429 Volume 6, Issue 1, May 2026 Impact Factor: 8.2

NkVs ,oa lhekar fdlkuksa dk çkFkfedrk & इन वर्गों के किसानों के लिए विशेष प्रावधान एवं सरल ऋण स्वीकृति प्रक्रिया सुनिश्चित की जाए।

xkeh.k Lrj ij çf'k{k.k ,oa f'kfoj & पंचायत स्तर पर नियमित किसान जागरूकता शिविर एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएँ।

cfdx çfØ;kvksa dk ljyhdj.k & ऋण आवेदन, स्वीकृति एवं वितरण की प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और समयबद्ध बनाया जाए।

fMftVy lyVQ,e dk foLrkj & मोबाइल ऐप, ऑनलाइन पोर्टल एवं डिजिटल सेवाओं के माध्यम से ऋण आवेदन एवं प्रबंधन को अधिक सुविधाजनक बनाया जाए।

nLrkostkdj.k esa yphykiu & आवश्यक दस्तावेजों की संख्या कम की जाए तथा वैकल्पिक सत्यापन प्रणाली विकसित की जाए।

fu;fer fuxjkuh ,oa eY;kadu & योजना के प्रभाव का समय–समय पर मूल्यांकन किया जाए तथा आवश्यकतानुसार सुधारात्मक कदम उठाए जाएँ।

cSd&fdlku leUo; esa lq/kkj & बैंक कर्मचारियों को किसान हितैषी व्यवहार के लिए प्रशिक्षित किया जाए, ताकि किसानों को बेहतर मार्गदर्शन मिल सके।

lanHkZ lwph

1. मेहता, डी., त्रिवेदी, एच. एवं मेहता, एन. के. (2016), भारतीय किसान क्रेडिट कार्ड योजनाः एक विश्लेषणात्मक अध्ययन, ब्रॉड रिसर्च इन अकाउंटिंग, नेगोशिएशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, खंड 6, अंक 1, पृ. 23–27।
2. गांधीमाथी, एस. एवं सुमैया, एम. (2015), भारत में किसान क्रेडिट कार्ड प्रणाली के वितरण की भूमिका, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मैनेजमेंट एंड सोशल साइंस, खंड 3, अंक 2, पृ. 464–472।
3. पाटिल, आर. डी. (2014), भारत में केसीसी योजना के माध्यम से वित्तीय समावेशन में वाणिज्यिक बैंकों की भूमिका, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशनल रिसर्च, खंड 3, अंक 5, पृ. 31–46।
4. शर्मा, ए., चौधरी, एस. एवं स्वर्णकार, वी. के. (2013), मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में लाभार्थी किसानों पर केसीसी योजना के प्रभाव का अध्ययन, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ साइंस एंड रिसर्च, खंड 2, अंक 1, पृ. 154–157।
5. चटर्जी, एस. (2015), कृषि ऋण सुधारों का कृषि परिणामों पर प्रभावः भारत में किसान क्रेडिट कार्ड कार्यक्रम से साक्ष्य।

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429 Volume 6, Issue 1, May 2026 Impact Factor: 8.2

6. मिश्रा, जे. एवं चौधरी, ए. के. (2021), किसान क्रेडिट कार्ड और भारत में वित्तीय समावेशन पर इसका प्रभाव, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ साइंटिफिक एंड मैनेजमेंट रिसर्च, खंड 5, पृ. 80–86।
7. कुमार, ए., सोनकर, वी. के. एवं आदित्य, के. एस. (2023), ग्रामीण भारत में किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऋण के प्रभाव का आकलनः पूर्वी भारत से साक्ष्य, यूरोपियन जर्नल ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च, खंड 35 (3), पृ. 602–622।
8. चंदा, ए. (2020), किसान क्रेडिट कार्ड योजना का मूल्यांकनः बिहार और भारत के लिए कुछ निष्कर्ष, अर्थनीतिः जर्नल ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी एंड प्रैक्टिस, खंड 19 (1), पृ. 68–107।
9. बिस्ता, डी. आर., कुमार, पी. एवं माथुर, वी. सी. (2012), किसान क्रेडिट कार्ड योजना की प्रगति और प्रदर्शनः बिहार का एक अध्ययन, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स रिसर्च रिव्यू, खंड 25 (1), पृ. 125–135।
10. वेंकटेश, आर. (2015), किसान क्रेडिट कार्ड योजना की पहुँच और प्रभाव, इंटरनेशनल जर्नल इन मैनेजमेंट एंड सोशल साइंस, खंड 3 (5), पृ. 270–284।
11. भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की रिपोर्ट
12. नाबार्ड की वार्षिक रिपोर्ट
13. आरबीआई की रिपोर्ट